भारत का योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना- PDF अभी डाउनलोड करें!

योजना आयोग (Planning Commission) भारत सरकार की मुख्य एजेंसी थी, जो पांच साल की योजनाओं के माध्यम से देश में आर्थिक और सामाजिक विकास की देखरेख करती थी। योजना आयोग के बारे में कई ऐसी जानकारियां थीं, जिन्हें अभी भी विभिन्न सरकारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसलिए यदि आप Railways RRB Group D, IBPS PO, IBPS Clerk, SSC CGL और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हैं तो योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताओं को जानना बेहद आवश्यक है। इसलिए योजना आयोग के बारे में विस्तार से जानने के लिए यह लेख अंत तक पढ़ें और इस लेख को पीडीएफ में डाउनलोड करना ना भूलें।

योजना आयोग के बारे में जाने

15 मार्च 1950 को स्थापित योजना आयोग एक सरकारी निकाय थी, जो देश की आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए योजना बनाया करती थी। योजना आयोग का मूल उद्देश्य मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ाकर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना था। योजना आयोग एक सलाहकार निकाय के रूप में संचालित थी। इसका नेतृत्व प्रधान मंत्री करते थे और आमतौर पर पूर्णकालिक उपाध्यक्ष हुआ करता था।

योजना आयोग की आवश्यकता

- योजना आयोग ने देश और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- योजना आयोग ने देश की भौतिक पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन करने और ऐसे संसाधनों को बढ़ाने की संभावना की जांच करने की ज़िम्मेदारी संभाली।
- योजना आयोग ने देश के संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना बनायी, उपलब्ध और संभावित संसाधनों दोनों के साथ।
- आयोग की दो प्रमुख जिम्मेदारियां थी- पहली प्राथमिकताओं का निर्धारण करना और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना तथा दूसरी कई योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का नि्र्धारण करना।

पंचवर्षीय योजना

- 1947 की आजादी के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के अलावा अन्य विकल्प नहीं बचा था। इसलिए राजनीतिक नेताओं को देश के तत्कालीन हालात के अनुसार अर्थव्यवस्था का चयन करना था व आर्थिक नियोजन भी तैयार करना था। जिससे पंचवर्षीय योजनाओं की शुरूआत हुई।
- आर्थिक योजना के तहत सरकार द्वारा योजनाबद्ध सामान्य और विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्र के संसाधन आवंटित करना मुख्य कार्यों में से एक था। जिस तरह से नाम स्वयं से ही बात स्पष्ट हो जाती है, भारत में यह योजनाएं पांच साल की अवधि के लिए बनाई गयी थी।
- पांच साल की योजना परिप्रेक्ष्य योजनाओं के मूल रूप से अल्पकालिक संस्करण हैं। एक परिप्रेक्ष्य योजना एक दशक या बीस साल तक की देश के दीर्घकालिक लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करती है।
- भारत में बनाई गई पांच साल की योजनाओं में आर्थिक नियोजन का विचार रूस (तब यूएसएसआर) से प्रेरित था।
- पांच साल की योजनाओं की धारणा के बाद, भारत ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं जारी की हैं। 12 वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी थी क्योंकि भारत सरकार ने पांच साल की योजनाओं को लॉन्च करना बंद कर दिया है और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग नाम की एक थिंक टैंक लॉन्च किया है।

testbook.com

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56):

1. यह योजना हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी।
2. इसने कृषि, प्रोडक्शंस, सिंचाई, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन के सुधार पर जोर दिया।
3. यह योजना सफल साबित हुई क्योंकि इस योजना के कारण कृषि उत्पादन में 3.6% की दर से बढ़ोत्तरी हुई थी।
4. भाखड़ा-नंगल, हीराकुंड और मेट्टूर बांध की प्रमुख बांध परियोजनाएं इस योजना अवधि के दौरान शुरू की गई थीं।
5. इस योजना अवधि के अंत तक, 1956 में, पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भी शुरू किए गए थे।
6. सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की गई थी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना(1956-61):

1. यह योजना 'महालनोबिस मॉडल' पर आधारित थी।
2. इस योजना ने औद्योगिक उत्पादों और तेजी से औद्योगिकीरण के घरेलू उत्पादन पर जोर दिया।
3. भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र की शुरूआत इस योजना के तहत ही की गयी थी।

4. इस योजना की लक्षित विकास दर 4.5% और वास्तविक विकास दर 4.27% थी।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) :

1. तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि और उद्योग की वृद्धि पर जोर दिया गया।
2. इसे 'गाडगिल योजना' के रूप से भी जाना जाता है।
3. इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय व कृषि उत्पादन में 30% तक की वृद्धि करना था।
4. लेकिन 1962 में चीन व 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध तथा खराब मौसम के कारण भारत अपना यह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया था।
5. इस योजना की लक्षित विकास दर 5.6% थी लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.4% थी।

प्लान हॉलीडे (1966-69):

1. तीसरी योजना की विफलता व भारत पाकिस्तान के बीच हुए बड़े युद्ध के कारण सरकार 'प्लान हॉलिडे' घोषित करने के लिए मजबूर थी।
2. इस अवधि के दौरान तीन वार्षिक योजनाएं तैयार की गई।
3. कृषि व इसकी संबद्ध गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी।

testbook.com

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74):

1. इस योजना ने कृषि विकास और भारत में हरितक्रांति पर जोर दिया।
2. 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
3. इस योजना की लक्ष्य वृद्धि दर 5.6%थी लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 3.3 % थी।.

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78):

1. इस योजना के तहत के रोजगार को बढ़ावा, मुद्रास्फीति की जांच, गरीबी उन्मूलन (गरीबी हटाओ) और न्याय पर ज़ोर दिया।
2. योजना का मसौदा प्रमुख राजनयिक 'डी.पी.धर' द्वारा तैयार किया गया था।
3. यह कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था।
4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरूआत की गयी।

CURRENT AFFAIRS
FASTEST WAY TO PREPARE
CURRENT AFFAIRS
GET IT ON Google Play

5. 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' लॉन्च किया गया।
6. जनता पार्टी के सरकार में आते ही इस योजना को चौथे वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया यानि कि 1978 में।
7. इसकी लक्षित वृद्धि दर 4.4% थी और वास्तविक वृद्धि 4.4% थी।

रोलिंग प्लान(1978-80):

1. जनता पार्टी सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और नई छठी पंचवर्षीय योजना(1978-1983) पेश की।
2. इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने 1980 में सत्ता में आने के बाद इस योजना को फिर से खारिज कर दिया और एक नई छठी योजना बनाई।
3. पहली वाली योजना रोलिंग योजना के नाम से जानी जाती थी।
4. रोलिंग प्लान की अवधारणा 'गुन्नार मिर्डल' द्वारा बनाई गयी थी।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85):

1. इस पंचवर्षीय योजना से आर्थिक उदारीकरण की शुरूआत हुई।
2. यह योजना बुनियादी ढांचे में बदलाव व कृषि पर समान रूप से केंद्रित थी।
3. छठी पंचवर्षीय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी।
4. इसकी लक्षित वृद्धि दर 5.2% थी और वास्ततिक वृद्धि दर 5.4% थी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना(1985-90):

1. इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक व अनाज की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसर पैदा करना था।
2. इस योजना के तहत 1989 में जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की गयी।
3. यह योजना सफल रही तथा इसका लक्षित वृद्धि दर 5.0% और वास्तविक वृद्धि दर 6.01% थी।

वार्षिक योजनाएं (1989-91और 1991-92):

1. राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस अवधि के दौरान कोई पांच वर्षीय योजना लागू नहीं की गयी थी।
2. 1990 और 1992 के बीच अवधि के लिए सिर्फ वार्षिक योजनाएं ही लागू की गयी थी।

3. 1991 में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा, उस वक्त केवल 1 अरब अमेरिकी डॉलर के भंडार देश के पास बचे थे। उस समय डॉ.मनोमहन सिंह ने मुक्त बाजार सुधार को लॉन्च किया, जिसने लगभग राष्ट्र को दिवालिया होने के कगार से वापस ले आया। यहीं से भारत में निजीकरण और उदारीकरण की शुरूआत हुई।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97):

1. इस योजना ने उद्योगों के आधुनिकीरण की दिशा में काम किया।
2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, गरीबी में कमी, रोजगार के अवसर पैदा करना व बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था।
3. इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी और वास्तविक वृद्धि दर 6.8% थी।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002):

1. इस पंचवर्षीय योजना ने पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने, गरीबी कम करने, कृषि उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी।
2. इसके अलावा **न्याय व समानता के साथ विकास पर** भी जोर दिया गया।
3. स्थिर कीमतों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी लाई गयी।
4. सभी लोगों को भोजन व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।
5. जनसंख्या पर नियंत्रण करना।
6. इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 6.5% व वास्तविक वृद्धि दर 5.40% थी।

दसवी पंचवर्षीय योजना (2002-07):

1. दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002- 07) में जीडीपी वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रही. इस योजना का उद्देश्य 'देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना' तथा 'अगले दस वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना' था.
2. योजना के दौरान प्रतिवर्ष 7-5 अरब डालर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया. योजना अवधि में पांच करोड़ रोजगार अवसर सृजन सहित साक्षरता, शिशु मृत्य-दर, वन विकास के बड़े लक्ष्य रखे गए.
3. दसवीं पंचवर्षीय योजना को इस लिहाज से भी उल्लेखनीय माना जा सकता है कि भारत उच्च (सात प्रतिशत से अधिक) वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट की पटरी पर आ गया. इस योजना में 7.7 प्रतिशत की औसत सालाना वृद्धि दर अब तक किसी योजना में 'सर्वोच्च वृद्धि दर' थी.
4. लक्षित वृद्धि दर 8.1% थी और वास्तविक वृद्धि दर 7.3% थी।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12):

1. इस योजना का मुख्य लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10% तक करना था तथा 12 वीं योजना में इसे 10% बनाए रखना था ताकि 2016 तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो सके।
2. राजीव आर्ययोगी स्वास्थ्य योजना शुरू की गई।
3. 70 लाख नए रोजगार के नए अवसर पैदा किए गए।
4. शिक्षित बेरोजगारी को 5% से कम करना था।
5. 5% से कम शिक्षित बेरोजगारी को कम करना।
6. 5% से अधिक वनावरण में वृद्धि।
7. 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिंगानुपात की दर को 2011 तक 935 करना और इसे 2016-17 तक इजाफा करते हुए 950 तक पहुँचाना।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17):

1. इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेजी से, अधिक समावेशी और सतत विकास के उद्देश्य के साथ 8.2% की वृद्धि हासिल करना था।
2. इसका उद्देश्य कृषि में 4 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करना और गरीबी को 10 प्रतिशत तक कम करना करना था।
3. स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और आधारभूत संरचना विकास इस योजना का मुख्य केंद्र थे।

योजना आयोग की कमियां

योजना आयोग की कुछ कमियां थीं जो आधुनिक भारत के लिए पुरानी थी। आइए जानते हैं कि व क्या कारण थे जिसने भारतीय योजना आयोग को अपर्याप्त व पुराना बना दिया था।

- स्वतंत्रता के बाद, भारत एक युवा देश था जिसमें कई संसाधनों की कमी थी। इन योजनाओं ने हमें कई संसाधनों और बहुत सारा पैसा संरक्षित करने में मदद की। योजना आयोग ने निर्दिष्ट किया कि कौन से उद्योगों को बढ़ाना चाहिए, किसे आगे आना चाहिए, किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए आदि। जो एक समाजवादी मॉडल था। सरकार ने अर्थव्यवस्था के हर पहलू को नजरअंदाज कर दिया।

- भारत ने उन समय से काफी प्रगति की है और अब एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहां सरकार अर्थव्यवस्था में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है और इससे बाजार की अधिकांश हिस्सेदारी संचालित हो जाती है। इस तरह की पृष्ठभूमि में योजना आयोग पुराने तरीकों से ही काम कर रही थी इसलिए योजना आयोग ने अर्थव्यवस्था के हर पहुलओं को नजरअंदाज कर दिया था।
- योजना आयोग की उपस्थिति में शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ। योजना आयोग ने खर्च की जाने वाली धन राशि, राज्यों को आवंटित करने वाले संसाधन आदि के बारे में निर्णय लेने पर पूरा नियंत्रण आयोग का था।

- इसने वित्त आयोग के क्षेत्र में हस्तक्षेप शुरू कर दी, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है।
- गुजरते समय के साथ, प्रधान मंत्री के साथ-साथ कैबिनेट को इसके समानांतर ला दिया। जो लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक प्रवृत्ति साबित हुआ।
- उन वर्षों में जहां यूपीए सत्तारूढ़ पार्टी थी, पर्यावरण मंत्रालय और योजना आयोग ने गैर-कांग्रेस राज्यों में गैर-योजना व्यय से इनकार करना शुरू कर दिया।
- यूपीए सरकार द्वारा राजनीतिक क्रोनियों के लिए इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा। आयोग नौकरशाहों से भी भरा था, जो केवल सामान्यवादी थे। जबकि भारत को 21 वीं शताब्दी की समस्याओं से निपटने के लिए विशिष्ट विषयों में विशेषज्ञों की आवश्यकता थी।

नए भारत के लिए योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन -

- केंद्र सरकार ने योजना आयोग के प्रतिस्थापन के रुप में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग(नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफारमिंग इंडिया) की स्थापना की।
- नीति आयोग, योजना आयोग के विपरीत एक थिंक टैंक या फोरम की तरह कार्य करेगा, जिसने पांच साल की योजनाओं को लागू किया है और आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए संसाधनों को आवंटित करेगा।
- नीति आयोग के परिषद में भारत के 29 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी- एक डिप्टी चेयरमैन, विशेषज्ञों की टीम होगी जो सीधे प्रधान मंत्री से संपर्क करेगी। जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं।
- योजना आयोग,नीति आयोग के विपरीत, राष्ट्रीय विकास परिषद को रिपोर्ट करता था।
- नीति आयोग व योजना आयोग में सबसे बड़ा अंतर यह है कि योजना आयोग प्रत्येक राज्य के बीच सामान्य दृष्टिकोण था व सभी शक्तियां केंद्रीकृत थी, नीति आयोग ने जमीनी स्तर पर कार्य करने का निर्णय लिया व वहीं राज्यों की भागीदरी भी बढ़ाई।

हमें आशा है कि आपको योजना आयोग पर यह लेख पसंद आया है। सामान्य ज्ञान पर अपनी पकड़ और अधिक मजबूत करने के लिए ऐसे अन्य लेखों को भी पढ़ें।

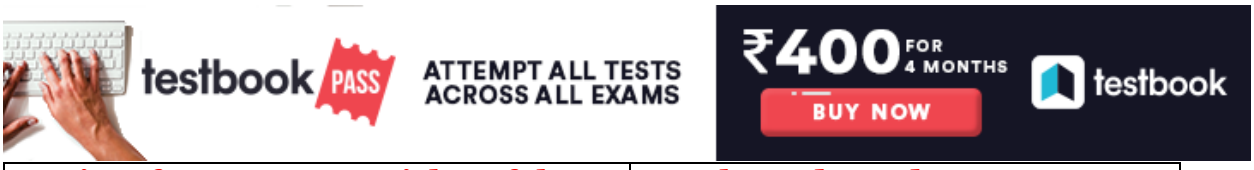

List of Important Articles of the Constitution of India	Banks and Headquarters – GK Notes in PDF
Important Regulatory Bodies in India	UNESCO World Heritage site in India
Indian States & Capitals	List of Stock Exchanges in India

हम सब जानते हैं कि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, इसलिए अपनी अध्ययन के माध्यम से अपनी तैयारियों को तेज करें।

Solve Practice Questions for Free

इसके अलावा, टेस्टबुक पर अपने संदेहों को दूर करने के लिए अपने साथी उम्मीदवारों और हमारे विशेषज्ञों से बात करें:

Go to Testbook Discuss

testbook.com